विनिर्माण हब के रूप में उभरता भारत

मेक इन इंडिया पहल भारत में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और अनुसंधान के द्वारा नवाचार को अपनाने और समृद्ध करने का एक सतत प्रयास है। योजना के द्वारा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तर पर कंपनियों से महत्वपूर्ण रुचि और निवेश का आदान-प्रदान हुआ है, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान मिला है। विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान से विशेष आर्थिक क्षेत्रों और औद्योगिक गलियारों के समर्थन से बुनियादी ढांचा मज़बूत हुआ है।

-डॉ. सचिन गुप्ता
-डॉ. पीयूष गोयल

भारत में अर्थव्यवस्था के मजबूत विकास, व्यापार के समग्र दृष्टिकोण में सुधार और देश को एक वैश्विक केंद्र के रूप में बदलने के लिए भारत में बनाओ- *मेक इन इंडिया* कार्यक्रम जैसे क्रांतिकारी विचार की शुरुआत और इस बहुआयामी अभियान की नींव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 25 सितंबर, 2014 को रखी गई।

भारत सरकार के प्रयासों से देश में महत्वपूर्ण निवेश, निर्माण, संरचना तथा नवाचार के साथ-साथ संस्थाओं में अपेक्षित सुविधाओं के विकास के लिए मजबूत बुनियादी सुविधाएं, व्यापार तथा विनिर्माण के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। *मेक इन इंडिया* मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश में

लेखक क्रमशः मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में सहायक आचार्य एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली में वैज्ञानिक हैं।
ई-मेल : sachinguptabusadm@gmail.com

भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली

मेक इन इंडिया का प्रतीक चिह्न (लोगो)

मेक इन इंडिया प्रतीक चिह्न को वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था। यह प्रतीक चिह्न वर्ष 1957 के कॉपीराइट अधिनियम तथा वर्ष 1999 के ट्रेडमार्क तथा वर्ष 2000 के डिज़ाइन अधिनियम के अंतर्गत इसे सुरक्षा एवं डिज़ाइन के पंजीकरण के तहत संरक्षित करता है, जिसके लिए भारत सरकार के पास स्वामित्व और उपयोग के लिए अनुमति का प्रावधान है।

सूत्रों के मुताबिक प्रतीक चिह्न में सिंह का चयन ना सिर्फ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न अशोक चक्र का हिस्सा है, बल्कि इसे साहस, ताकत और बुद्धिमता के लिए भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक और अर्थशास्त्री भारत की विशाल अर्थव्यवस्था और उसकी सुस्त चाल के मद्देनज़र हाथी की संज्ञा देते आए हैं, लेकिन आक्रामक विदेश नीति और निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से काफी विचार-विमर्श के बाद प्रतीक चिह्न में सिंह का चयन हुआ, जो एक सकारात्मक पहल और कार्यक्रम के लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

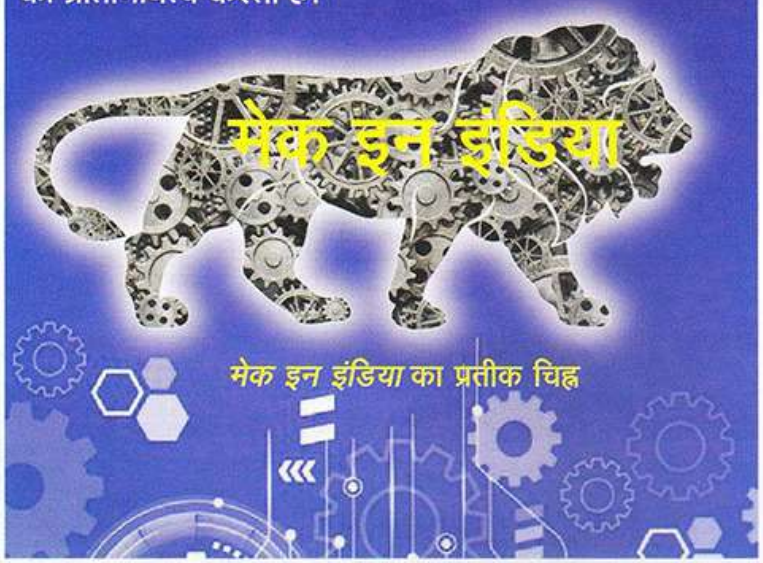

मेक इन इंडिया का प्रतीक चिह्न

उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इसके कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:-

- **निवेश प्रोत्साहन :** इसके तहत निवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सकारात्मक माहौल देकर व्यापार को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे घरेलू और विदेशी निवेशकों की मदद के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में उदारीकरण के साथ निकासी प्रक्रियाओं में सुधार, और विशेष निवेश सुविधा इकाइयों के निर्माण को बढ़ावा देना शामिल है।
- **विनिर्माण क्षेत्र :** *मेक इन इंडिया* का उद्देश्य विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद के योगदान को बढ़ाना और रोज़गार के अवसर पैदा करना है। विनिर्माण के संदर्भ में यह योजना ऑटोमोबाइल, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसका उद्देश्य भारत की जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाना और औद्योगिक गलियारों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम से मज़बूत बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इसके अतिरिक्त, कार्यबल को विनिर्माण उद्योग के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी लागू किए जाते हैं।
- **बुनियादी ढाँचा विकास :** इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों की सफलता और विकास के लिए एक बुनियादी ढाँचा तैयार करना तथा विनिर्माण गतिविधियों के लिए माल की आवाजाही को सुगम और सुनिश्चित करने के लिए परिवहन नेटवर्क, स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक्स पार्क, औद्योगिक गलियारे जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना है।
- **कौशल विकास :** यह *मेक इन इंडिया* कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो उद्योगों और विनिर्माण इकाइयों में सक्षम कार्यबल की आपूर्ति के लिए कौशल विकास के कार्यक्रमों पर ज़ोर देती है। युवाओं और श्रमिकों को शिक्षित और कुशल बनाने के साथ उनकी क्षमताओं में सुधार और रोज़गार देने तथा एक सफल और कुशल उद्यमी के रूप में उनकी क्षमताओं में सुधार करना शामिल है।
- **नवाचार और अनुसंधान :** नवाचार किसी नवीन क्रिया को सम्पन्न करने की प्रक्रिया है। 'नवाचार' अविष्कार से भिन्न है, जिसमें नवीन सामग्रियों, नवीन विधियों तथा नवीन तकनीकों का पता लगाते हैं, जबकि नवाचार में इनका उपयोग नवीन उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। नवाचार से देश की विनिर्माण क्षमताओं में उत्कृष्टता, उद्योगों में नए उत्पाद, उद्यमशीलता (एंत्रप्रन्योरशिप) और स्टार्टअप के माध्यम से निवेश और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल है। सरकार नवाचार के माध्यम से प्रौद्योगिकी-संचालित गतिविधियों के समर्थन के लिए कई अनुसंधान पार्कों, प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे युवा स्वयं के उद्योग लगाकर देश के विकास में सहयोग प्रदान कर सकें।
- **बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) की सुरक्षा :** कोई भी नया अविष्कार या नवाचार को बढ़ावा देना अविष्कारकर्ता के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर निर्भर है। अतः सरकार द्वारा व्यवसायों के लिए आविष्कारों, पेटेंट और ट्रेडमार्क की सुरक्षा को आसान बनाने, आईपीआर कानून और प्रवर्तन प्रणालियों की सुरक्षा को मज़बूत करने की पहल जारी है।
- **डिजिटल इंडिया :** *मेक इन इंडिया* की पहल डिजिटल भारत योजना के साथ जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य भारत को एक समृद्ध डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का लाभ देते हुए हर किसी को इंटरनेट सुविधा देना तथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं और विनिर्माण

मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर बनता भारत

मेक इन इंडिया पहल से डिजिटल विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकें अपनाने को प्रोत्साहन मिला है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जोड़ना तथा भारतीय कंपनियों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में आगे लाना है। भारत आज दुनिया की सबसे विस्तृत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सरकार द्वारा कई तरह के उपाय किए गए हैं, जिससे व्यापार और भारतीय अर्थव्यवस्था फल-फूल सकें। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उत्कृष्टता के साथ नवाचार-संचालित पहलुओं से जोड़कर भारत को वैश्विक स्तर पर विनिर्माण और नवाचार के केंद्रबिंदु के रूप में स्थापित करना और निवेश को प्रोत्साहित करके नौकरी के अवसर पैदा कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शामिल है।

की प्रक्रियाओं में एकीकृत लाभ, उत्पादकता, दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शामिल है।

***मेक इन इंडिया* ऐप :** 'भारत सहित पूरी दुनिया के लिए भारत में निर्माण' (*मेक इन इंडिया* फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड) थीम के तहत डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज (चुनौती) को अटल इनोवेशन मिशन-नीति आयोग के साथ मिल कर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए शुरू किया था, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। इस चुनौती में ऐसे भारतीय ऐप्स, जो पहले से ही देश में इस्तेमाल हो रहे थे, या जिसमें अपनी श्रेणी में ऐसे उत्पाद या उत्पादों को बनाने के लिए विश्व स्तर दृष्टि या विशेषज्ञता थी, की पहचान करना था।

इस योजना से भारत एक विनिर्माण हब के रूप में उभर रहा है, जो अभी सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 16% का योगदान दे रहा था, सरकारी लक्ष्यों के मुताबिक वर्ष 2020 तक उसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाना था। *मेक इन इंडिया* कार्यक्रम की शुरुआत के बाद भारत में निवेश के लिए यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहली पसंद बन चुका है। वर्ष 2015 में भारत ने अमेरिका और चीन को पछाड़कर 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया था।

विदेशी कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग लगाने से भारत के आयात बिल को कम करने और देश में रोज़गार सृजन में मदद मिली है। नीतियों के तहत सरकार ने अंतरिक्ष में 74 फीसदी; रक्षा में 49 फीसदी; समाचार तथा मीडिया में 26 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दी है। घरेलू स्तर पर बनाए गए उत्पाद, उत्पादों की गुणवत्ता तथा भारत में उत्पादों की बिक्री तथा निर्माण के साथ-साथ सबसे ऊपर के चयनित क्षेत्रों में सौ फीसदी एफडीआई की मंजूरी है।

विश्व बैंक के 2015 के व्यापार सूचकांक में 189 देशों में भारत 134वें स्थान से निकल कर 2016 में 130वें स्थान पर था। भारत विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 139 देशों की सूची में 38 वें स्थान पर पहुँच गया है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश की वजह से यह सुधार सम्भव हुआ।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी दर

विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वातावरण में महत्वपूर्ण चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर लचीली बनी हुई है। भारत की जीडीपी ग्रोथ और महंगाई वैश्विक रेटिंग के प्रमुख पैमाने हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान वास्तविक जीडीपी में वर्ष दर 7.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पूरे वर्ष में विकास दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान था, जबकि 2023-24 के लिए 6.6 प्रतिशत (दिसम्बर, 2022) तक रहने का आंकलन किया गया था, हालांकि बड़ी हुई मुद्रास्फीति के कारण जीडीपी औसतन 5.2 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया गया है।

***मेक इन इंडिया* योजना में शामिल प्रमुख क्षेत्र :** यह योजना 25 महत्वपूर्ण उद्योगों को लक्षित करती है, जो अर्थव्यवस्था के निम्न 25 क्षेत्रों पर केंद्रित है:-

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	13. चमड़ा
1. गाड़ियां	14. मीडिया और मनोरंजन
2. ऑटोमोबाइल अवयव	15. खनिज (मिनरल)
3. विमानन	16. तेल और गैस
4. जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी)	17. फार्मास्यूटिकल्स (दवा उद्योग)
5. रसायन (केमिकल)	18. बंदरगाह और शिपिंग
6. निर्माण	19. रेलवे
7. रक्षा विनिर्माण	20. नवीकरणीय ऊर्जा
8. इलेक्ट्रिकल मशीनरी	21. सड़क और राजमार्ग
9. इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ	22. अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान
10. खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रासेसिंग)	23. कपड़ा और परिधान
11. सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन	24. तापीय ऊर्जा (थर्मल एनर्जी)
12. पर्यटन और आतिथ्य	25. कल्याण

मेक इन इंडिया- निवेश, विनिर्माण और नवाचार : यह योजना देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने, निवेश, विनिर्माण और इनोवेशन (नवाचार) को शामिल कर आर्थिक विकास के लिए प्रमुख स्तम्भों के रूप में कार्य करती है। देश के औद्योगिक क्षेत्रों में विकास और विस्तार में असीमित सम्भावनाएं हैं, अतः योजना में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना, विनिर्माण क्षमताओं और सभी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। इस कार्यक्रम से निवेश प्रवाह में वृद्धि हुई है, विनिर्माण क्षमताओं में सुधार और विकास हुआ है। भारत वैश्विक विनिर्माण परिदृश्य में एक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो गया है, जो स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक है। बीते कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) द्वारा एक साथ 104 सेटेलाइट लॉन्च करने के बाद से लगातार इस क्षेत्र में परचम लहराने से भारत की धाक बढ़ी है।

ज़्यादातर भारतीय उद्योग पहले वस्तु निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों के निर्मित उत्पाद (प्रोडक्ट्स) पूरे भारत में बेचते थे, और उन पर ही निर्भर थे, जिससे उनको तो फायदा होता था, परंतु भारत में उद्योग नुकसान उठाते थे, और स्वदेशी उत्पाद बिक नहीं पाते थे। इस कार्यक्रम से रक्षा, रेलमार्ग, निर्माण, बीमा, पेंशन फंड और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में, भारत ने सक्रिय रूप से अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत किया है, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रास्ते खोल दिए हैं।

एक स्तंभ के रूप में यह योजना नए कारोबार शुरू करने के लिए कारोबारियों, उद्योगपतियों और लोगों को प्रोत्साहित करती है, और लाइसेंस तथा रेगुलेशन की प्रक्रिया आसान कर उद्योगों को कम टैक्स में ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें घरेलू और विदेशी फर्म दोनों ही बहुत रुचि ले रही हैं।

व्यापार (बिजनेस) करने के लिए ई-बिज़ पोर्टल प्लेटफार्म पर अलग-अलग उद्योगों से संबंधित जानकारियां एकत्रित की गईं हैं, जिससे 24 घंटे संबंधित जानकारी सेवाएं ली जा सकती हैं। इस अभियान की सफलता निरंतर कानूनी समायोजन, नए बुनियादी ढांचे के विकास, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर ध्यान आकर्षित करती है।

मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में अंतर : *मेक इन इंडिया* में भारतीय श्रम को नियोजित करना, भूमि का उपयोग करने के लिए पूंजी, प्रौद्योगिकी और निवेश के रूप में उत्पादन के विदेशी कारकों को निमंत्रण मात्र है। *मेड इन इंडिया* में उत्पादन के स्वदेशी कारक (घरेलू ब्रांड) यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक संसाधन को शामिल करना है, जिसकी घरेलू और विदेशी बाज़ार में पहचान है। अर्थात् जिसमें *मेड इन इंडिया* लिखा होता है। दोनों ही नीतियां अपने-अपने तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचा सकती हैं। *मेक इन इंडिया* को एक निश्चित समय के लिए बढ़ावा दिए जाने से घरेलू उद्यमियों के लिए घरेलू स्तर पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे, और *मेक इन इंडिया* से *मेड इन इंडिया* की ओर बदलाव सम्भव होगा, तथा विनिर्माण क्षेत्र को आत्मनिर्भरता तथा वैश्विक मान्यता प्राप्त हो सकेगी।

इनोवेशन (नवाचार) और *मेक इन इंडिया* अभियान एक साथ काम करते हैं, क्योंकि कई उद्योगों में नवाचार नए उत्पादों को बनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रसिद्ध प्रबंधन सलाहकार, पीटर ड्रकर के अनुसार "नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट साधन

है- अतः वह कार्य जो संसाधनों को धन पैदा करने की नई क्षमता प्रदान करता है"। भारत में नवाचारों को सुनिश्चित और सक्षम किए बिना *मेक इन इंडिया* पहल सफल नहीं हो सकती। जीई ग्लोबल इनोवेशन बैरोमीटर 2016 के अनुसार भारतीय कंपनियों एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा नए उत्पादों और सेवाओं के लिए दायर पेटेंट की संख्या, दुनिया भर में दायर पेटेंट का मात्र 2% है। निष्कर्षतः *मेक इन इंडिया* पहल यह जानती और मानती है कि उत्पादन या विनिर्माण क्षेत्र की दीर्घकालिक वृद्धि और स्थिरता के लिए भारतीय नवाचार महत्वपूर्ण है। उद्यमिता, अनुसंधान एवं विकास, सहयोग, प्रौद्योगिकी को अपनाने और कौशल विकास को बढ़ावा देकर इस अभियान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, जो नवाचार को तो प्रोत्साहित करता ही है, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है, और वैश्विक बाज़ार में भारत की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। *मेक इन इंडिया* अभियान किस तरह से प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करता है, उसे निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:-

उद्यमिता और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र : नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक संपन्न उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देता है। अतः संभावित व्यावसायिक उद्यमियों, वैज्ञानिकों और किसी भी क्षेत्र में इनोवेशन (नवाचार) को समझने और उत्पाद विकसित करने के लिए *स्टार्टअप इंडिया* जैसी पहल न केवल सहायता, धन, सलाह और नेटवर्किंग संभावनाएं प्रदान करती हैं, बल्कि इस कार्यक्रम के द्वारा प्रौद्योगिकी संचालित स्टार्टअप के विकास और रचनात्मक व्यावसायिक विचारों के निर्माण को भी बढ़ावा देती है।

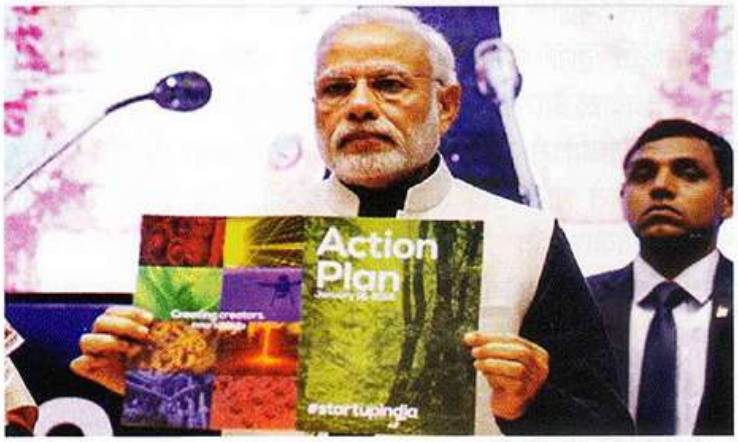

प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' स्टार्टअप कार्ययोजना

भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी-बाइरैक) एक उद्योग-शैक्षणिक अंतरफलक (इंडस्ट्री-अकादमिक इंटरफ़ेस) है, जो बायोटेक फर्मों में नवाचार उत्कृष्टता लाने और अनुसंधान में मौजूदा अंतराल को पाटने तथा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से नवीन, उच्च गुणवत्ता वाले किफायती उत्पादों के विकास की सुविधा, विशेष रूप से स्टार्टअप और एसएमई (लघु एवं मध्यम उद्यम) की रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार क्षमताओं को प्रोत्साहित करने में मदद करती है।

बाईरैक के प्रौद्योगिकी पोर्टल पर नवाचार, अन्वेषकों, प्रौद्योगिकी परिपक्वता के चरण, प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) मैप के साथ विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा समर्थित व्यावसायीकृत किफायती उत्पादों और उनके क्षेत्रवार विवरण को उनकी वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यह पोर्टल उद्यमियों, क्षेत्र विशेषज्ञों, निर्माताओं और निवेशकों के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करता है।

अनुसंधान और विकास (आर.एंड.डी) पर फोकस : इसके माध्यम से सरकार अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर व्यय करके नवाचार को प्रोत्साहित करती है, जिसके लाभ से विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक विकास, उत्पाद, नवाचार और प्रक्रिया सुधार को बढ़ावा देना शामिल है। कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार के द्वारा टीकों (वैक्सीन) की खोज और निर्माण से भारत को पूरे विश्व में अपनी विनिर्माण क्षमताओं को दिखाने में सफलता हासिल हुई है।

सहयोग और साझेदारी : *मेक इन इंडिया* योजना व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान संगठनों के बीच साझेदारी और सहयोग पर ज़ोर देती है, जिससे एक ऐसा वातावरण स्थापित हो, जो सहयोग के द्वारा ज्ञान के साझाकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से विचारों और जानकारियों के प्रवाह को आपस में बढ़ा सके।

प्रौद्योगिकी को अपनाना : योजना भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकियों और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर बल देती है। भारत को आज हम एक मज़बूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पारिस्थितिकी तंत्र और उत्कृष्टता के प्रस्तावित केंद्रों के साथ रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में *मेक इन इंडिया* दृष्टि को एक नए रूप और भविष्य के अवसरदाता के रूप में देख रहे हैं। इस योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य निर्यात और रोज़गार को बढ़ावा देना तथा भारत की 2 खरब (ट्रिलियन) डॉलर अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 2022 तक 25 प्रतिशत तक बढ़ाना था, और 100 करोड़ नौकरियों का सृजन करना था, लेकिन योजना के इन दोनों ही मसलों पर सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भी यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और जीडीपी में वृद्धि दर से रोज़गार पैदा करने में मदद नहीं मिलेगी बल्कि इसके लिए दूसरे उपाय भी खोजने होंगें।

रेल और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में मेक इन इंडिया की पहल: सरकार ने दूसरे क्षेत्रों के साथ रक्षा उत्पादन में स्वदेशी को बढ़ावा देना शुरू किया, जिसके परिणाम सामने आने लगे हैं। रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत में निर्मित उत्पादों जैसे हल्का लड़ाकू

मेक इन इंडिया कार्यक्रम से बढ़ती भारत की सैन्य ताकत

विमान 'तेजस', कम्पोज़िट सोनार डोम पोर्टेबल टेलीमेडिसिन सिस्टम, अर्जुन टैंक के लिए प्रवेश-सह-विस्फोट, वरुणास्त्र टारपीडो, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के शिपयार्ड में बने दो ऑफशोर पैट्रोल वेसेल, जिसके नाम 'शचि' और 'श्रुति' रखे गए हैं, को लॉन्च किया है। स्कॉर्पीन श्रेणी की कलवरी और खांदेरी के बाद बनी तीसरी आईएनएस 'करंज' स्वदेशी पनडुब्बी *मेक इन इंडिया* कार्यक्रम की ही देन है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनी स्वदेशी 1.5 किलोग्राम की रक्षा बुलेट प्रूफ जैकेट को मंजूरी मिली है, जिससे 20 हज़ार करोड़ रुपये की बचत की सम्भावना है।

स्वदेशी उत्पादों के माध्यम से मेक इन इंडिया के ज़रिए रक्षा मंत्रालय को एक लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का लाभ हुआ है। आयुध कम्पनियों की भी आर्थिक दशा सुधरी है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) भारत में मेक इन इंडिया और तकनीकी हस्तांतरण (ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी) के अंतर्गत इस परियोजना को गति प्रदान कर रहा है। जापानी कम्पनी अपने ब्लूप्रिंट और कार्यप्रणाली को अपने भारतीय समकक्षों के साथ साझा करेगी, और बाद में मेक इन इंडिया योजना की शर्तों के अनुसार भारत में अपनी विनिर्माण क्षमताओं को भी मज़बूत करेगी। इन क्षेत्रों में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं।

मेक इन इंडिया से आधुनिक भारत की तस्वीर

सरकार के इन कदमों से कॉरपोरेट जगत में सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। जनवरी, 2015 के बाद से देश में इस योजना के तहत 700 से अधिक प्रस्ताव आ चुके हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर जीडीपी पैमाने पर भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, जिसमें इस योजना का बहुत बडा हाथ है।

मेक इन इंडिया योजना के 25 सितंबर, 2023 को 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत में वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वित्त वर्ष 2014-15 में 45.15 बिलियन डॉलर था। इन बीते वर्षों में बढ़कर दोगुना अर्थात् 83 बिलियन डॉलर हो गया है। यह निवेश 101 देशों से आया है, और भारत में 31 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में तथा 57 क्षेत्रों में निवेश किया गया है। 27 क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धियां हासिल की गई हैं। अगर भारत की वित्तीय स्थिति में लगातार सुधार और महंगाई लगातार कम होती है, तो वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी की ग्लोबल रेटिंग भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (सार्वभौमिक श्रण दर) को उन्नत (ऊपर) कर सकती है। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की सकारात्मकता को स्वीकारा है, जिससे रेटिंग को और उन्नत करने की उम्मीद की जा रही है।

कुल मिलाकर, मेक इन इंडिया पहल भारत में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और अनुसंधान के द्वारा नवाचार को अपनाने और समृद्ध करने का एक सतत प्रयास है। योजना के द्वारा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर कंपनियों से महत्वपूर्ण रुचि और निवेश का आदान-प्रदान हुआ है, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान मिला है। विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान से विशेष आर्थिक क्षेत्रों और औद्योगिक गलियारों के समर्थन से बुनियादी ढांचा मज़बूत हुआ है।

कौशल विकास पर ज़ोर एक सक्षम कार्यबल योजना है, जो सुनिश्चित करती है कि प्रोत्साहनों, सुधारों और नीतियों की श्रृंखला के माध्यम से एक ऐसा निवेशक-अनुकूल वातावरण बने जो नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ भारत में व्यापार को आसान बनाए, हालांकि यह एक सतत प्रक्रिया है। अभियान ने निवेश को आकर्षित करने, विनिर्माण विकास और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, और एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है, जो भारत में निवेश, विनिर्माण और नवाचार के द्वारा जन-जन की भागीदारी को सुनिश्चित कर सके और उन्हें देश के आर्थिक विकास में योगदान देने के योग्य बना सके। ❑